

आर्थिक बनाम राजनीतिक सम्पदा

- एन के त्रिपाठी

पिछले दिनों इंग्लिश प्रिंट मीडिया में एक मनोरंजक बहस नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया तथा ऑटोमोबाइल सेक्टर के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर्स (SIAM) के बीच छिड़ गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर का यह कहना है कि माँग कम होने के कारण उनकी गाड़ियों की बिक्री 30% घट गई है। उनका यह भी कहना है कि भारत के मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का 50% ऑटोमोबाइल सेक्टर है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे 10 लाख से ऊपर लोग इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे।

उन्होंने इसे न केवल मैनुफैक्चरिंग सेक्टर बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक बताया है। इस आधार पर उन्होंने सरकार से सीधे-सीधे यह माँग कर दी है कि इस सेक्टर को अब विशेष रियायतें दी जाएं, जिससे माँग बढ़ायी जा सकती है। अरविंद पनगढ़िया जी का यह कहना है कि सरकार के लिये किसी भी एक सेक्टर को अलग से हटकर रियायतें देना उचित नहीं होगा। उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर के आंकड़ों को भी अतिरंजित बताया है।

सिद्धान्त यह है कि हर सेक्टर पर अलग-अलग नीतियां बनाए जाने से पूरी अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ हो जाने की आशंका बनी रहती है। दूसरे शब्दों में उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को कोई बड़ी रियायत देने का विरोध किया है। मैं यहाँ पर दोनों पक्षों द्वारा दिए गए लंबे तकनीकी कारणों का विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा, केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे कर्णधारों को इन तथ्यों का गहराई से परीक्षण करना चाहिए। इससे भी अधिक यह आवश्यक है कि यह पता किया जाये कि वो कौन से मूलभूत कारण हैं जिनसे अर्थव्यवस्था में ऐसी विकृतियाँ सामने आ रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में निश्चित रूप से एक कठिन दौर से गुजर रही है तथा 5% जीडीपी दर के कारण आर्थिक मंदी के कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी है। मोदी सरकार इस समय राजनीतिक सम्पदा के शिखर पर बैठी है तथा तीन तलाक, धारा 370 और धमाकेदार विदेश नीति के कारण देश के बहुसंख्यक लोगों का ध्यान केवल उसी तरफ केंद्रित है। मोदी एवं BJP को इसका श्रेय दिया भी जाना चाहिए। परंतु यही राजनीतिक सम्पदा इस सरकार को यह मानने के लिए कहीं प्रेरित न कर दें कि अर्थव्यवस्था की स्थिति चुनावी राजनीति में कोई मायने नहीं रखती है।

BJP को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह केवल राजनीतिक मुद्दों पर ही ध्यान दे तथा उन्हें ही देश के मानसिक पटल पर रखे। यह मानसिकता देश के लिए घातक होगी। मोदी को यह भी स्पष्ट ध्यान में रखना चाहिए कि आज यदि विश्व भारत की ओर देख रहा है तो उसका केवल एक मात्र कारण भारत की उभरती हुई आर्थिक शक्ति और भारत का एक बहुत बड़ा मध्यमवर्गीय बाज़ार है। चीन से 13 वर्ष के बाद भारत ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया और अर्थव्यवस्था को तेज़ी दी।

देश पर जब घोर आर्थिक संकट आता है तो ऐसी स्थिति एक चुनौती के रूप में एक नया अवसर लेकर आती है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल एक बार नरसिंहा राव ने मनमोहन सिंह के माध्यम से सबसे साहसिक आर्थिक निर्णय इस कारण लिया क्योंकि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था भूतल को छू रही थी। भारतीय राजकोष से झाड़-पोंछ कर बचा खुचा सोना निकाल कर विदेशों में बँचा जा रहा था। नरसिंहा राव के समक्ष साहसिक कदम उठाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा था।

मोदी सरकार को भी उसी उत्साह से वर्तमान चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने राजनीतिक पराक्रम का उपयोग कर दूसरी पीढ़ी के सुधारों का साहसिक निर्णय लेना चाहिए। अभी हाल में 3 किस्तों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कुछ नीतिगत एवं प्रक्रियात्मक कदमों की घोषणा की है। ये कदम निश्चित रूप से सही दिशा में लिये गये हैं। परन्तु ये कदम वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के सामने बाल-डग के समान हैं। सभी समुन्नत देशों एवं हमारी आँखों के सामने देखते देखते शिखर पर पहुँचने वाले चीन की नीतियों से सीख लेते हुए हमें भी श्रम और भूमि सुधार के संबंध में कठोर निर्णय लेने होंगे। मोदी के घोर विरोधियों को भी यह भलीभाँति मालूम है कि कठोर आर्थिक निर्णय प्रजातंत्र में केवल एक सशक्त नेतृत्व ही ले सकता है। देश को मोदी जैसी राजनीतिक पूंजी बार बार आसानी से नहीं मिलने वाली है। मोदी ने 2014 में देश को समृद्ध बनाने का एक सपना दिखाया था और यदि उस सपने को उन्होंने साकार नहीं किया तो यह देश के साथ उनका बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। मोदी को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय में बैठे बाबुओं पर भरोसा करने के स्थान पर देश के सकारात्मक सोच वाले अर्थशास्त्रियों का सहयोग लेना चाहिए। देश आज आर्थिक क्षमताओं के चौराहे पर खड़ा है।

(लेखक मप्र पुलिस के डीजी पद से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।